उत्तराखंड उच्च न्यायालय

WPMS/824/2021 12 नवंबर, 2021 को

उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में

नैनीताल में

नवंबर, 2021 के 12वें दिन

पहले:

माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 824 2021

बीच में:

मैसर्स मैट्रिक्स एनवायर्नमेंटल, ए सोल

प्रोपराइटरशिप फर्म .....याचिकाकर्ता

(श्री पीयूष गर्ग, अधिवक्ता द्वारा)

और:

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

(श्री सी.एस. रावत द्वारा, राज्य/प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए सीएससी सीखा।)

निर्णय

उभयपक्षों के विद्वान वकील को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने जनजातीय कल्याण निदेशालय द्वारा जारी निविदा सूचना के अनुसार बोली प्रस्तुत की। उनकी तकनीकी बोली खारिज कर दी गई है. उनके अनुसार, उन्हें पता चला कि उनकी बोली उत्तरदाताओं के वेब पोर्टल के माध्यम से खारिज कर दी गई है, जहां यह प्रदर्शित किया गया था कि अधूरे दस्तावेज के कारण उनकी तकनीकी बोली खारिज कर दी गई है। इस प्रकार, व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

3. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। जवाबी हलफनामे के पैरा-10 में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की बोली निविदा सूचना के खंड 39 में निहित शर्तों की पुष्टि नहीं कर रही थी, क्योंकि याचिकाकर्ता का ईपीएफ पंजीकरण जुलाई, 2020 का था, जबकि खंड 39 के लिए आवश्यक था कि प्रत्येक बोलीदाता ईपीएफ में पांच साल पुराना पंजीकरण होना चाहिए। उक्त जवाबी हलफनामे के पैरा-11 में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता की बोली शर्तों की पुष्टि नहीं कर रही थी निविदा सूचना के खंड 36 में निहित है, हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पांच अनुभव प्रमाणपत्रों में से केवल चार वित्तीय वर्ष 2018-19 के संबंध में थे और एक वित्तीय वर्ष 2016-17 के संबंध में था; जबकि शर्त के अनुसार सभी प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2018-19 के संबंध में होने चाहिए। निविदा सूचना के खंड 37 में निहित शर्त के संबंध में, यह आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में, उस आवासीय विद्यालय के छात्रों की संख्या का भी खुलासा नहीं किया गया था जहां उन्होंने कथित तौर पर खानपान सेवा प्रदान की थी। जो अनिवार्य था. खंड 37 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष 2019-

20 के दौरान न्यूनतम 500 छात्रों को खानपान सेवा प्रदान करने का अनुभव होना चाहिए। जवाबी हलफनामे के पैरा-11 में, यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता की बोली शर्त संख्या के अनुरूप नहीं थी। निविदा नोटिस के 33 में प्रत्येक बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों (2016-17, 2017-18 और 2018-19) के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट की गई बैलेंस शीट जमा करने की आवश्यकता है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का कहना है कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने अपनी फर्म को वर्ष 2020 में ईपीएफ के साथ पंजीकृत कराया था, हालांकि उसने अपनी फर्म के पंजीकरण के समय पिछले पांच वर्षों का रिटर्न जमा किया था, इसलिए, उसकी बोली खारिज नहीं की जा सकती थी। इस ज़मीन पर.

5. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई दलील योग्यता से परे है। शर्त यह है कि किसी फर्म का ईपीएफ पंजीकरण पांच वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि फर्म पर्याप्त रूप से अनुभवी है और उसके पास उस परिमाण का काम करने के लिए जनशक्ति सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा है, जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

6. चूँकि याचिकाकर्ता की बोली निविदा सूचना की स्पष्ट शर्तों के अनुरूप नहीं थी, इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा उसकी बोली को गैर-उत्तरदायी घोषित करने के निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इन मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा न्यूनतम होना चाहिए और यह न्यायालय निविदा मामलों में नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय पर अपील नहीं कर सकता है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय । लिमिटेड , (2016) 16 एससीसी 818 में रिपोर्ट की गई है: -

"11. हाल ही में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम एसएलएल-एसएमएल (ज्वाइंट वेंचर कंसोर्टियम) मामले में)5 कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए इस न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि किसी निविदाकार की बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने में नियोक्ता या परियोजना के मालिक की निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हस्तक्षेप की अनुमति केवल तभी है जब निर्णय लेने की प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण हो या किसी का पक्ष लेने के उद्देश्य से हो। इसी प्रकार, निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि निर्णय इतना मनमाना या अतार्किक न हो कि न्यायालय यह कह सके कि यह निर्णय ऐसा है जिस तक कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी तर्कसंगत और कानून के अनुसार काम नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, निर्णय लेने की प्रक्रिया या निर्णय विकृत होना चाहिए न कि केवल दोषपूर्ण या ग़लत या गलत।

12. द्वारकादास मार्फटिया एंड संस बनाम पोर्ट ऑफ बॉम्बे में यह माना गया कि संवैधानिक अदालतें निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित हैं। टाटा सेल्युलर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया7 एक कदम आगे बढ़ गया और यह माना गया कि यदि किसी निर्णय को चुनौती दी जाती है (वैध प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लिया गया है) , तो संवैधानिक अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं यदि निर्णय विकृत है। हालाँकि, संवैधानिक

अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप करने में संयम बरतें और उन्हें प्रशासनिक प्राधिकारी के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। जैसा कि सेंट्रल कोलफील्ड्स में उल्लिखित है, इसकी पुष्टि जगदीशमंडल बनाम उड़ीसा राज्य में की गई थी।

13. दूसरे शब्दों में, निर्णय लेने की प्रक्रिया या प्रशासनिक प्राधिकारी के निर्णय से असहमति मात्र संवैधानिक न्यायालय के हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है। संवैधानिक न्यायालय द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया या निर्णय में हस्तक्षेप करने से पहले दुर्भावना, किसी का पक्ष लेने का इरादा या मनमानी, तर्कहीनता या विकृति की सीमा को पूरा किया जाना चाहिए।

14. हमें सावधानी के उन शब्दों को दोहराना चाहिए जो इस न्यायालय ने ठीक उसी समय से कहे हैं जब रमनदयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण का फैसला लगभग 40 साल पहले हुआ था, अर्थात्, निविदा दस्तावेजों में इस्तेमाल किए गए शब्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है o निरर्थक या अतिश्योक्तिपूर्ण - उन्हें अर्थ और उनका आवश्यक महत्व दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, बोली दस्तावेजों की धारा III के खंड 4.2 (ए) में "मेट्रो" शब्द का उपयोग और सामान्य बोलचाल में इसके अर्थ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

7. याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका में निविदा नोटिस की किसी भी शर्त को चुनौती नहीं दी है।

8. इस मामले को देखते हुए, इस न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

9. तदनुसार, रिट याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

(मनोज कुमार तिवारी, जे.)